



# SEWA Rashtriya Patrika

SEWA's Mouthpiece Integrating Women Workers in National Development

## सेवा राष्ट्रीय पत्रिका

राष्ट्रीय विकास में कामगार महिलाओं का संयोजता सेवा का मुखपत्र

Issue No.: 1; April 2016

Advisors: Manali Shah, Sonia George, Shikha Joshi

Internal circulation

**“THERE IS NO WORK, YET THE GRIND OF WORK IS KILLING ME....”**

**M**y experience in SEWA made me meet and listen to the great women of India working in fields, forests, mines, homes, on mountains, roads, shores or in the markets. These women are great; they are better fighters against poverty than their men. They have calculative, stable, forward looking strategies to deal with their own environment. Women are most committed proponents of our future.

However, today the grind of work is killing them.... Their work is endless, yet invisible....

There is a growing need of women to find work and the enormous problems they face in the labour market. It is essential to emphasize differentially greater load of handicaps they suffer from, high fertility putting restrictions on their mobility, lack of transferable skills, lack of markets and techniques and lack of access to assets, capital and tools.

Over time, traditional trades and traditional support systems are breaking down. More and more households are becoming asset less making it more difficult for women of participate in economic activities. This is worsened by current globalization and mechanization. In the current scenario, women have become vulnerable as livelihoods become growingly unstable amidst mounting poverty.

I hope that the Rashtriya Patrika of SEWA will demonstrate how women workers can and do to build strong, vital organizations around issues that are relevant to them, find viable solutions out of their own experiences and in the process change our society and environment in a healthy, respectful, nonviolent and sustainable way ..... And achieve much needed VOICE, VISIBILITY and VALIDIATION.

**Ela R. Bhatt**  
Founder, SEWA

**“मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी मैं काम के बोझ के नीचे दबी हुई हूँ”**

**से**वा में काम करते हुये मुझे भारत की उन महान महिलाओ से मिलने, बातचीत करने व काम करने का अनुभव हुआ जो जंगल, खेत-खलिहान, खदान, पहाड़ों, बाजारों में काम करती है। ये महिलायें महान ही है क्योंकि इनमे अपने पुरुषों की तुलना में गरीबी के खिलाफ लड़ने की बेहतर क्षमता है। इनके पास वातावरण से निपटने की गुणात्मक व स्थाई व अग्रसर होनेवाली रणनितियाँ हैं। भविष्य के लिये महिलायें ही सबसे अधिक कटिबद्ध समर्थक होती हैं।

बहरहाल आज काम का बोझ उन्हें धीरे-धीरे मार रहा है.....। उनका काम अंतहीन है परन्तु अदृश्य आज महिलाओं की बढ़ती जरूरतों में काम को खोजना और श्रम बजार में कठिन समस्याओं का सामना है। अत्यन्त आवश्यक है, कि उनको विकलांग बनाने वाले विभिन्न प्रकार के बोझ जिनके तले वे दबी है, जैसे उच्च पैदावर क्षमता, उनकी हलचल पर रोक लगाती है। कौशल को बदलने की क्षमताओ का अभाव, बाजार और नई तकनीकियों का अभाव पूंजी, औजार और सम्पति तक उनकी पहुँच का अभाव।



उनकी असुरक्षा समय के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पारम्परिक व्यवसाय और पारम्परिक सहायक प्रणालियाँ खत्म हो रही हैं। अधिक घरों में सम्पत्तियाँ कम होती जा रही है। जिससे न केवल महिलायों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना कठिन हो रहा है, अपितु पारिवारिक स्थिति भी बेहद खराब हो रही है।

यह खराब परिस्थितियों वर्तमान में हो रहे वैश्वीकरण और मशीनीकरण के कारण हैं। वर्तमान में परिदृश्य ये अजिविका कमाना मुश्किल हो रहा है। और परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ती जा रही है। परन्तु अन्त में मुझे आशा है कि सेवा की राष्ट्रीय पत्रिका यह साबित करने में सक्षम होगी की महिला श्रमिको को कैसे अपने को मजबूत बना सकती हैं। उनके महत्वपूर्ण संगठन उनके आस पास के मुद्दों का हल वो कैसे अपने अनुभवों के आधार पर ढूँढ़ती है, और इस प्रक्रिया में हमारे को समाज व पर्यावरण को स्वस्थ सम्मानपूर्वक अहिंसक व स्थाई तरीकों में बदलती है। इससे आवाज, पहचान और मान्यता मिलती है जिसकी ज्यादा जरूरत है।

**ईला र. भट्ट**  
संस्थापिका, सेवा



# WE WON U-WIN CARDS THAT GIVE OUR IDENTITY TO WORLD

## *Sewa Women Rummaged Through Red Tape For Their Rights!*

It was a day to remember when hundreds of women from the unorganized sector held the coveted 'UWIN' or 'Unrecognized Workers Identification Number' cards in their hands in SEWA office in Ahmedabad. Their smiles were contagious, their energy electrifying. After years of working anonymously rolling incense sticks, picking waste, vending vegetables and doing mason work on construction sites, these women had finally got their identity. They were now a recognized work force of Gujarat with a name, profession and identity which government recognizes for social security.

Founder of Sewa Elaben Bhatt distributed the first batches of cards on February 29 who said the UWIN cards have come after a great deal of struggle and years of fighting for rights of women workers. "Women should always remember their `naam, kaam, gaam' (name, village, profession). We should no longer be identified just as somebody's wife, mother or sister. Take pride in your identity, your work".

Manali Shah who has been lobbying for the cause of UWIN cards with the labour ministry said that each card was not just a card, it was a living person!

"This card is identity of a worker, it makes her work count and gives her voice and visibility", said Manaliben who said that out of 9.7 lakhs issued by the government, over 1.25 lakh were facilitated by Sewa for its members.

Interestingly, when it comes to fighting for their rights, Sewa women can cut all red-tape. For getting UWIN cards too, a team of 17-women plunged deep into the sea of files stacked in the storeroom of the state labour commissioner office to look for over 1.25 lakh forms filled by their sisters to get UWIN cards from the state government.

The UWIN cards were to be provided by the state as it implemented state rules of the Social Services Act 2008. The UWIN cards promised not only identity cards to women working in informal sector but also benefit of state welfare schemes namely `Ma Amrutam' scheme that provides cashless treatment of up to Rs 2 lakh for



critical diseases even in private hospitals as well as `Ma Vatsalya' scheme which provides cashless treatment of up to Rs 1.2 lakh to children.

The Sewa sisters filled the forms which were to be linked with Adhar cards and duly submitted to the labour department. In between, this project collapsed after Supreme Court ordered that these forms should not be linked with Adhar as it would make personal details of too many people public. Only beneficiaries of PDS and MNREGA should be linked with Adhar forms.

Since Sewa sisters had duly filled forms with photographs, they met the minister as well as labour commissioner and insisted that they should be provided the UWIN cards. Labour commissioner voiced his dilemma— the forms were collected and stacked along with lakhs of other forms and it would be difficult to find them!

Sewa sisters took up the challenge and plunged into the storeroom. "Finding our forms in lakhs of papers stacked was finding needle in a haystack but we did it. With our sarees we wiped dust off the files. Since we had attached pictures, it helped to find our forms", says Sewa member Ramilaben. It took 17 days but all forms were found.

Shardaben Parmar vouches the ID card offered her the promise security. "My husband was diagnosed with oral cancer. While the social security scheme linked with UWIN card has not become operational as yet, the hospital accomodated my husband's case in another welfare scheme and waived off Rs 50,000 on the basis of the UWIN card. There is hope for a better future". Amen.



# “हमने यूविन कार्ड के ज़रिये विश्व में अपनी पहचान को जीत लिया”

सेवा की बहनों ने अपने अधिकारों के लिये लाल फीता काटा

उस दिन को याद करती हूँ जब हज़ारों महिलाओं ने सेवा कार्यालय अहमदाबाद में अपने हाथों में ‘यूविन’— यानि असंगठित कामगार पहचान नंबर.... के कार्ड को अपने हाथों में लिया था। उनकी मुस्कान बहुत ही तेजस्वनी थी, उनमें गजब की ऊर्जा थी। कई सालों से लगातार अग़रबत्ती बेलना, कचरा बीनना, सब्जी बेचना व निर्माण कार्य में मजदूरी करने के बाद आखिरकार उनको उनकी पहचान मिल ही गई अब वे ऐसी पहचानी हुई श्रमशक्ती हैं जो गुजरात में अपना नाम, व्यवसाय व पहचान के साथ विद्यमान है। जिसे सरकार ने सामाजिक सुरक्षा हेतु दी है।

सेवा की संस्थापिका श्री इला भट्ट ने 29 फरवरी को यूविन-कार्ड की प्रथम खेप का विवरण करते हुये कहा कि यूविन-कार्ड वर्षों से चल रहे संघर्ष व महिला श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई का परिणाम है। “महिलाओं को हमेशा अपना ‘नाम, काम, गाँव’ को याद रखना चाहिये। अब हमें उनकी पहचान को किसी की पत्नी, माँ या बहन की तरह नहीं करना चाहिये। अपने काम को अपनी पहचान बनाना ही हमारा गौरव है।”

मनाली शाह जो कि यूविन-कार्ड को लेकर श्रम मंत्रालय के साथ लोबिंग कर रही थी उन्होंने कहा कि कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं थे, जीते जागते इन्सान है। “यह कार्ड कामगारों की पहचान है यह उनके काम की गणना करता है और उन्हें दृश्यता देता है।” उन्होंने बताया की 9.7 लाख कार्ड जो सरकार ने जारी किये हैं। उसमें से 1.25 लाख कार्ड को सेवा के सहयोग से अपने सदस्यों को मिले।

सुखद जब उनके अधिकारों की लड़ाई की बात आती है। सेवा की सदस्य महिलाओं लाल फीता भी काट सकती है। यूविन कार्ड मिलने के लिये सेवा की 17 बहनों की टीम ने राज्य के श्रम व रोजगार विभाग के आफिस स्टोर रूम के 1.25 लाख आवेदनों को बहुत ही गहरे समुन्दर में से देखा ताकि उनकी सदस्य बहनों को यूविन कार्ड राज्य सरकार द्वारा मिल सके।

2008 के सामाजिक सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर यूविन कार्ड राज्य सरकार द्वारा दिये जाने थे। यह यूविन कार्ड केवल पहचान कार्ड ही नहीं बल्कि जो महिलायें असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं उनको राज्य की कल्याणकारी योजना “मां अमृतम” जिसमें गम्भीर बीमारियों के केशलेस इलाज हेतु 2 लाख रुपये की सुविधा मिलेगी। “मां वात्सल्य” योजना से 1.25 लाख का केशलेस इलाज की सुविधा बच्चों को मिलेगी।

सेवा की कार्यकर्ता बहनों ने आवेदन भरे जो कि आधार कार्ड से जुड़े थे जिन्हे श्रम विभाग में जमा किया गया। परन्तु बीच में यह काम बन्द हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया की यह आवेदन आधार कार्ड से नहीं होना चाहिये। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी को काफी व सार्वजनिक करता है। केवल मनरेगा व खाद्य सुरक्षा के फायदे लेने वालों को आधार से जोड़ना चाहिये। चूकि सेवा की बहनों ने फोटो के साथ आवेदन भरे थे, वे श्रममंत्री व श्रम सचिव से व दूसरे श्रम ऑफिसरों से मिली व जोर दिया कि उन्हें यूविन कार्ड देना चाहिये। श्रम आयुक्त ने कहा कि सभी आवेदनों को मिला दिया गया है और उनको खोजकर अलग करना कठिन है।

सेवा की बहनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया व आवेदन खोजने में लग गई। रमीला बेन ने बताया कि लाखों आवेदनों में से सेवा की सदस्य बहनों के आवेदन खोजना कचरे के ढेर में से आलपीन खोजने जैसा था। परन्तु हमने किया। हमने हमारी साडी से फाईलों की धुल को झाडा। क्योंकि हमने फोटो लगाये थे उसने हमे आवेदन खोजने में मदद ही हमने 17 दिन तक काम किया पर सभी आवेदनों को खोज लिया।

शारदा बेन परमार ने बताया की यह पहचान कार्ड ने हमें हमारी सुरक्षा का वादा दिया है। “मेरे पति को मुह का कैंसर निकला जब कि अभी यूविन कार्ड में सामाजिक सुरक्षा की योजना को यूविन कार्ड के आधार पर जोडा नहीं गया है परन्तु अस्पताल वालो ने मेरे पति के केस को दूसरी कल्याणकारी योजना से जोडकर 50,000 रूपयो को इलाज किया। हमें हमारे उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद है।”



# SEWA HOLDS PUBLIC HEARING FOR RESOLVING ISSUES PLAGUING WOMEN FISH WORKERS IN KERALA

## *Recommendations Include 'Women Only' Fish Markets And More Matsyafed Buses To Transport Women Fish Vendors*

Trivandrum 16th Month, 2016

### PLIGHT OF FISHING COMMUNITY WOMEN IN KERALA

A detailed survey undertaken by SEWA of fish vendors, their access to fish and major issues faced by them in fish markets in Kerala gave an in-depth insight into the problems plaguing women fish workers. Study revealed that significant changes in the sector over the last 6-7 years—significantly more men are now dominating fish vending business, competition of fresh fish with poor quality frozen that has adversely impacted price fetched by fresh produce from the sea.

### DISCUSSION WITH AFFECTED WOMEN

Findings of the study were discussed with women fish workers including fresh fish and frozen fish sellers in February 2015. Both groups understood that they were all victims of changes in mechanisms of fishing business in last few years. Business has become more capital intensive now. Bigger boats are used for fishing and thus landings have become more centralized. Fish is frozen during long voyages which is then dumped in harbours. This frozen fish is then transported to shores for sale to women vendors in the fishing communities. Since consumers buy on limited budgets, there is higher demand for frozen fish. The big question posed to them was: 'Would they be willing to sit in separate markets so that consumers could have the choice to buy either fresh or frozen fish?'

### THE PUBLIC HEARING

SEWA organized a public hearing on problems of women fish workers. The hearing was held on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_.

Sonia, secretary of the SEWA Union Kerala, threw light on issues faced by over 5000 women involved in fishing business in earning livelihood in three coastal districts of Thiruvanthapuram, Quilon and Kasargod.

Mercy, a young woman, apprised the jury of huge debt incurred as her husband adopted new methods of catching fish like outboard engines, GPS, larger nets and powerful lights. "We borrowed Rs.3 lakhs five years ago and have now fallen into a debt of Rs. 10 lakhs. All they catch seems to go to the companies who produce technology and oil to run the engines. We are left in huge debts as we now fish not to sustain ourselves but the companies. Why does the government not control this?", asked a desperate Mary to the jury.

Philomi spoke about the traditional knowledge of the small scale fishing community and highlighted that they could manage to fish large catches without any modern equipment. Philomi further said that the traditional knowledge, accumulated for generations is based on the rhythms of nature and thus is sustainable. She reiterated that this knowledge and people should be protected.

Punitha, Carmel, Mary, Varghese and Jaya then spoke of the problems they faced in accessing fish to sell. Punitha, who only procures fresh fish, highlighted how she has to travel to different shores to get fresh fish incurring high transport costs. Carmel spoke about competition at the Quilon harbor to buy fish at the auctions which are marred by heated arguments on weights and quality by the wholesale merchants. Jaya spoke about the bad quality frozen fish that comes to their part of the seashore in insulated vans from distant harbours. "Since frozen fish is much cheaper than the fresh fish, it is adversely affecting market of fresh fish", she said.

Stella spoke about the ordeal they have to face in reaching the market. They are not allowed on buses the bus conductors treat them very badly. She shared her painful experience of being literally thrown out of the bus with her container. Achamma spoke about the Matsya Fed bus that takes them to the harbor at Quilon and brings them back to the market. She said that it is a great service but there are only 4 such busses in the state. Kochu Theresia spoke about the astronomical





costs of hiring private vehicles, which drains them of all their earnings. She demanded that the Matsya Fed should provide a special bus for over 100 women vendors from her village.

Selvarani, Silvamma and Punitha shared their horrible experiences in the market. She highlighted that women are treated very roughly in the market and the head load workers extort large sum of money just to carry baskets from the autos at the market. They also demand festival allowances as well. Another thing that troubles them is the high market taxes. The working conditions at the market are very poor. There is no running water at the markets and no toilets are available. The renovation work at the markets is done so badly that there is not enough space for the consumers and the tiled floors are so slippery that consumers are afraid to come in. They spoke about the poor drainage for the water run off.

Biggest problem for them is that the prime places are occupied by the male merchants. Finally Annamary, who had put up a big fight at the market where she sells fish explained in detail how it was they, the members of SEWA, who had managed to get the panchayat to renovate the market as they had to sit out sun. When the panchayat finally did construct the market, the women were not allowed a space to sit under the shelter, which were occupied by the men. The reason for this is the auctioning policy for prime space in markets. The man who wins the bid gets control of sheltered space for decades. He has made his own rules and he treats the women very badly. This man is a big merchant of frozen fish and he has engaged male vendors who sell the fish for him. These men do not pay any tax and they occupy the prime place in the market.

Alphonsa and Vimala spoke about the fate of the women who sell dry fish. They explained that the only fish they get to dry these days comes from the vehicles that bring frozen fish.

Since this fish is of bad quality and is often put in ammonia or formalin, it has no shelf life even when it is dried. Hence they have to dispose of it fast and the price they get very low price for their fish. Moreover, they have to go to distant markets to sell this fish - to areas where no other fish reaches.

To wind up, Amala spoke about the living conditions of the fishing community. In many areas there is no access to potable water and people have to buy it. There are no drainage and sanitation facilities and thus many areas are constantly water logged causing a major health hazard. Several villages face threats of erosion and houses are damaged during the rains. This is caused by the stone retention walls that are being built all along the coast to save the coast from erosion. She claimed this is not an effective method and that because of this the sea gets polluted by inland pollutants. The life of people living on shores has become hell because of this.

Sita, who compered the Hearing, ended it by saying that the policy for modernizing the fishery had led to adverse effects on people's work and food. It seemed that the government was concerned only about increasing fish production and not about the lives of millions who are involved in small scale fish production. Hence it is important for the local and state governments to find ways to solve these issues and ensure the rights to livelihood.

The Jury listened attentively and gave their verdict which is summarized below:

- Maintaining the quality of fish is an important aspect of food safety. The Department of Food Safety will train fisherwomen in aspects of quality management. Such experiments are presently being undertaken in north Kerala and the same can be adopted in Thiruvanthpuram as well. This must eventually be conducted through the entire value chain.

■ When women are trained, means of branding the high quality fish can also be undertaken.

■ 'Women Only' Markets selling only good quality fish should be developed in other districts to facilitate the process of informing the consumers of good quality fish available at these markets. This would ensure that these women would get better

■ Markets are developed by the Fisheries Department/ Fisheries Corporation and handed over to the Municipal Corporation or local bodies. In future, criteria will be developed when handing over markets to local bodies so that the rights of women vendors are safeguarded and that the maintaining of infrastructure of sanitation, lighting and waste disposal are made mandatory.

■ Discussion should be held between the women vendors and the head load workers through their representative organizations. The Head Load Workers Welfare Board will proactively help to see that the workers do not charge extra. The board will also help sort out other disputes and reduce the harassment of the women.

■ As the market is their workplace, any harassment should be dealt with according to the Harassment at the Workplace Act.

■ The Matsyafed presently runs a few buses for women vendors at great cost. It will make efforts to introduce more buses on routes that will be viable - particularly from Adimalathura to Neyyatinkara.

■ All women should actively participate in gram sabhas so that they can demand their rights from the local government and stand united against the

marginalization and harassment they face.

■ More comprehensive data is required about women who work in different aspects of fishing business. The Fisheries Department should find ways of collecting more authentic data so that planning and budgeting for this sector is also more meaningful.

■ Presently there is a mismatch between the loan schemes of various departments and the needs of the women. In collaboration with SEWA efforts will be made to develop creative participatory alternatives that can be more beneficial to women.

■ All technical institutions should reach out more to women's groups to develop their capacities in financial management and quality control. CSR support could also be sought for this.

■ More attention should be given to the implementation of the Street Vendors Act so that the street vendors are not arbitrarily evicted and are ensured various facilities guaranteed under the Act like portable shelters, access to public toilets & water, garbage clearance etc.

■ Js. M.R.Hariharan Nair, (Chairperson of the Jury), Chairman, Fisheries Debt Relief

■ Ms. Anupama T.V, IAS, Food Safety Commissioner

■ Dr. K. Ambady, IIS, Managing Director, Coastal Development Authority

■ Mr. Kishore Kumar, Managing Director, Matsyafed

■ Ms. Lethy. M, Additional Director, Fisheries

■ Ms. Sujatha Viswanathan, Secretary in Charge, Head Load Workers Board

■ Dr. Nikita Gopal, Principal Scientist, CIFT

■ Shri A. J. Vijayan, Social Activist



# केरल में महिला मछली कामदारों की समस्याएं सुलझाने हेतु जन सुनवाई

सिर्फ बहनों की मछली मार्केट, मत्सयफेड बसों का सुझाव

## मछली कामगारों की व्यथा-कथा

महिला मत्स्य कामदारों को होने वाली परेशानियों को गहराई से समझने के लिए सेवा संस्था ने केरल की महिला मछली व्यवसायियों को मछली पकड़ने तथा बेचने के लिए बने मछली बाजार में उन्हें होने वाली परेशानियां जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चला कि इस क्षेत्र में पिछले 6-7 वर्षों में काफी बड़े परिवर्तन आए हैं। जैसे मछली बेचने के व्यवसाय में अब पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा है तथा ताजी मछली और कम गुणवत्ता वाली शीत-गृह की मछली को बेचने में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से समुद्र में से पकड़ी जाने वाली ताजी मछली के मूल्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

## प्रभावित महिलाओं के साथ विचार-विमर्श

फरवरी 2015 में सर्वेक्षण के दौरान मिले परिणामों की चर्चा महिला मत्स्य कामदारों के साथ की गई जिस में ताजी मछली तथा शीतगृह की मछली बेचने वाले दोनों समूहों की महिलाएं शामिल थीं। दोनों समूहों ने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों से मछली व्यवसाय की तकनीकी में आने वाले परिवर्तनों का उन सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस व्यवसाय में अब ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है। मछली पकड़ने में अब बड़ी नावों का उपयोग किया जाता है जिससे मछली उतारने की जगहें केंद्रीयकृत हो गई हैं। लम्बी समुद्री यात्रा के दौरान पकड़ी गई मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें कम तापमान पर रखा जाता है। तथा बंदरगाहों पर ही उतारा जाता है। मत्स्य समुदाय की महिला व्यापारियों को बेचने के लिए ये शीतगृह की मछलियां इन बड़े बंदरगाहों से छोटे-छोटे तटों तक पहुंचाई जाती हैं। शीतगृह की ये मछलियां सस्ती होने से ग्राहक इन्हें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। जिससे इनकी मांग ज्यादा रहती है। अब प्रश्न यह उठता है, कि क्या शीतगृह की मछलियां बेचने वाले व्यापारी अलग बाजार में बैठकर मछली बेचने को तैयार होंगे ताकि ग्राहक को ताजी या शीतगृह की मछली खरीदने की पसंदगी मिल सके।

## जन सुनवाई

महिला मत्स्य कामदारों की परेशानियों को समझने व उन्हें दूर करने के लिए सेवा संस्था ने एक जन सुनवाई का आयोजन किया। इसमें सेवा केरला की महासचिव सोनियाजी ने त्रिवेन्द्रम, क्विलोन तथा केसरगढ़ तटीय जिलों की मछली व्यवसाय से आजीविका कमाने वाली 5000 से ज्यादा महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। एक कम उम्र की महिला मर्सी ने जन सुनवाई कर रही समिति को बताया कि उसके पति ने पांच साल पहले बड़े इंजन, जी.पी.एस, मछली पकड़ने के बड़े जाल तथा दूर तक रोशनी के लिए बड़ी लाइटों खरीदने के लिए तीन लाख रूपयों का कर्ज लिया था जो आज बढ़कर दस लाख रूपये हो गया है। वो लोग जितना कमाते हैं वो सारा धन इन तकनीक तथा इंजन चलाने के लिए तेल बनाने वाली बड़ी कम्पनियों को चला जाता है। उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद को नहीं परन्तु इन कम्पनियों को जिंदा रखने के लिए पैसा कमा रहे हैं। एक अन्य महिला मेरी ने पूछा कि क्या सरकार इन कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती है?

एक महिला फिलोमी ने छोटे स्तर पर मछली पकड़ने वाले समुदाय की पारम्परिक विद्या के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि वे इस विद्या का उपयोग बिना किसी नई तकनीक का उपयोग किए बड़े स्तर पर मछलियां पकड़ने में भी कर सकते हैं। फिलोमी ने आगे कहा कि यह ज्ञान कई पीढ़ियों से इकट्ठा हुआ है। इसलिए दीर्घकालिक है तथा इस ज्ञान और

यह ज्ञान रखने वाले लोगों का संरक्षण जरूरी है। पुनीथा, कार्मल, मेरी, वर्गीस तथा जया ने मछलियों को बेचते समय उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। केवल ताजी मछली बेचने वाली पुनीथा ने बताया कि ताजी मछली खरीदने के लिए उसे कई सारे तटों पर जाना पड़ता है। जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है। कार्मल ने क्विलोन तट पर ताजी मछलियों की नीलामी के दौरान उसके भार तथा गुणवत्ता को लेकर थोक व खुदरा व्यापारियों में होने वाली बहस तथा होड़ के बारे में बताया। जया ने दूर बंदरगाहों से उनके तट पर आने वाली कम गुणवत्ता युक्त शीतगृह की मछलियों के बारे में बात करते हुए कहा कि सस्ती होने की वजह से इन मछलियों ने ताजी मछली के बाजार पर विपरीत प्रभाव डाला है। स्टीला ने बाजार तक पहुंचने में आने वाली परेशानियों का जिक्र किया। उसने कहा कि बसों के कंडक्टर उन्हें बस में नहीं चढ़ने देते तथा उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उसने बताया कि एक बार उसे उसके सामान के साथ बस से बाहर फेंक दिया गया था। अयम्मा नाम की महिला ने उन्हें क्विलोन बंदरगाह तक ले जाने तथा वापस बाजार तक लाने के लिए चलने वाली "मत्स्य फेड" बसों के बारे में बताते हुए कहा कि हालांकि यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। परन्तु राज्य में ऐसी सिर्फ चार बसें ही चलती हैं। कोचू श्रेणीया नाम की एक अन्य महिला ने निजी वाहन चालकों द्वारा लिए जाने वाले ऊर्चे किराये के बारे में बोलते हुए कहा कि उनकी सारी कमाई इस किराये में ही चली जाती है। उसने मांग करते हुए कहा कि उसके गांव से लगभग सौ महिला व्यापारियों को लाने ले जाने के लिए मत्स्य फेड द्वारा विशेष बस चलानी चाहिए। सेल्वारानी, सिलवामा तथा पुनीथा ने मछली बाजार के उनके भयानक अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा कि बाजार में उनके साथ बहुत ही रूखा व्यवहार किया जाता है तथा आटोरिक्षा से बाजार तक मछली का क्रेट लाने के लिए मजदूर बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। उन्होंने तय्यार पर बोनास मिलने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनसे लिया जाने वाला बाजार कर भी बहुत ज्यादा है। बाजार में काम करने की सुविधाएँ बहुत ही खराब है। बाजार में पानी तथा शौचालय भी नहीं है। बाजार में निर्माण तथा मरम्मत कार्य इतना खराब है कि ग्राहक के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है तथा फर्श पर लगी टाइल्स फिसलन भरी होने के कारण ग्राहक उन पर चलने से डरते हैं इसलिए ग्राहक उन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। पानी के निकास की भी कोई व्यवस्था बाजार में नहीं होने से पानी भरा रहता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि बाजार में मुख्य बेचने के स्थानों पर पुरुष व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। अंत में अन्नामेरी नाम की महिला ने बाजार में छायादार स्थान बनाने के लिए सेवा संस्था के साथ मिलकर पंचायत के खिलाफ लड़ी गई उनकी लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया। जब पंचायत ने बाजार में छायादार स्थान बनवाए तब पुरुष व्यापारियों ने उन जगहों पर कब्जा कर लिया। इसका कारण बाजार में मुख्य स्थानों पर बैठने के लिए होने वाली नीलामी प्रथा है। जो आदमी इस नीलामी में ज्यादा पैसा बोलता है वह कई वर्षों तक इस जगह पर बैठता है। वह अपने स्वयं के नियम बनाता है तथा महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। यह व्यक्ति शीत-ग्रह की मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी है तथा कई पुरुष व्यापारी इसके लिए मछलियां बेचने का काम करते हैं। ये आदमी बाजार में प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं तथा कोई टैक्स भी नहीं देते हैं। अलफोन्सा तथा विमला नाम की महिलाओं ने सुखी मछलियां बेचने वाली महिलाओं की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुखाने वाली मछलियां शीत-ग्रह की मछलियां लाने वाली गाडियों में ही आती हैं। कम गुणवत्ता तथा अमोनिया व फोर्मेलिन में रखी होने की वजह से सूखने के बाद भी ये जल्दी सड़ जाती है। जिससे वे इन मछलियों को ज्यादा समय तक नहीं रख पाने की वजह से कम मूल्य पर ही बेच देते हैं। इन्हें जल्दी से जल्दी बेचने के लिए कई बार उन्हें दूर-दूर जाकर भी बेचना पड़ता है जहाँ इन मछलियों का बाजार नहीं हो।

मत्स्य समुदाय के जीवन-स्तर के बारे में बताते हुए अमाला ने कहा कि उनके पास पीने योग्य पानी भी नहीं है यह पानी उन्हें खरीदना पड़ता है। गटर लाइन तथा सफाई का अभाव होने से पानी भरा रहता है। जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई गाँवों में बारिश के मौसम में मिट्टी तथा





मछलियों का बाज़ार नहीं हो।

मत्स्य समुदाय के जीवन-स्तर के बारे में बताते हुए अमाला ने कहा कि उनके पास पीने योग्य पानी भी नहीं है यह पानी उन्हें खरीदना पड़ता है। गटर लाइन तथा सफाई का अभाव होने से पानी भरा रहता है। जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई गाँवों में बारिश के मौसम में मिट्टी तथा घरों के बह जाने का खतरा रहता है क्योंकि तटों को बहने से रोकने के लिए पत्थरों की दीवार बना दी गई है। उसने कहा कि यह उपयुक्त तरीका नहीं है क्योंकि इससे समुद्र में आन्तरिक प्रदूषण बढ़ा है तथा इसकी वजह से तटों पर रहने वाले लोगों का जीवन नरक बन गया है।

सीता ने बताया कि मत्स्य व्यवसाय में काम में ली जाने वाली आधुनिक तकनीक का लोगों के काम तथा भोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसा लगता है कि सरकार को केवल मछली उत्पादन बढ़ाने में रुचि है परन्तु छोटे स्तर पर मछली उत्पादन करने वाले असंख्य लोगों के जीवन की उसे कोई चिन्ता नहीं है। स्थानिय तथा राज्य सरकार को चाहिए कि इन परेशानियों को दूर करने के उपाय ढूँढे तथा लोगों के जीने का अधिकार सुनिश्चित करें।

जन सुनवाई करने वाली समिति ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना तथा अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि—

■ मछली की गुणवत्ता को बनाए रखना खाद्य सुरक्षा विभाग, मछली पकड़ने वाली महिलाओं को मछली की गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों के बारे में प्रशिक्षण देगा। अभी ऐसे प्रयोग उत्तरी केरल में चल रहे हैं ऐसे ही तिरुअनन्तपुरम में भी लागू किए जा सकते हैं। मछली की गुणवत्ता बनाए रखने की श्रृंखला के सभी स्तरों को इसमें शामिल किया जाएगा।

■ महिलाओं के प्रशिक्षित होने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली मछली का पंजीकरण तथा प्रचार प्रसार भी किया जा सकेगा।

■ दूसरे जिलों में भी केवल उच्च गुणवत्ता की मछलियां बेचने के लिए ऐसे बाज़ार जाएंगे जो केवल महिला व्यापारियों के लिए होंगे। जिसमें ग्राहक को यह पता चल जाएगा कि इन बाज़ारों में केवल उच्च गुणवत्ता वाली मछलियां ही मिलती हैं। ऐसा होने पर महिला व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ जाएगी।

■ मत्स्य विभाग या मत्स्य कोर्पोरेशन ऐसे बाज़ारों का निर्माण करेंगे तथा बाद में इन बाज़ारों को स्थानिय लोगों के समूह या म्युनिसिपल कोर्पोरेशन को सौंप देंगे। इसके लिए भविष्य में नियम बनाए जाएंगे महिला व्यापारियों के हितों की रक्षा हो तथा सफाई, प्रकाश व कचरा-निस्तारण को आवश्यक बनाया जा सके।

■ महिला व्यापारियों तथा माल ढोने वाले मजदूरों के संगठन के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए। इन मजदूरों के कल्याण के लिए गठित बोर्ड के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग महिला व्यापारियों से ज्यादा मजदूरी न ले सकें। साथ ही बोर्ड को चाहिए कि वह महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों को रोकें तथा सम्बन्धित विचारों का समाधान

करें।

■ कार्यस्थल होने की वजह से बाज़ार में होने वाली किसी भी ज्यादती के सन्दर्भ में कार्यस्थल पर ज्यादती के खिलाफ बने कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।

■ 'मत्स्यफेड' अभी केवल कुछ ही महिलाओं के लिए बसे चला रहा है। जिनका किराया ज्यादा है। इसे चाहिए कि वह अन्य जगहों विशेषकर अदीमालाथुरा से नैयाटिनकारा तक ज्यादा बसे चलाए जिनका किराया व्याजबी हो।

■ सभी महिलाओं को ग्राम सभा में सक्रिय भाग लेना चाहिए ताकि स्थानिय सरकार के सामने वे अपनी मांगें रख सकें तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के खिलाफ संगठित होकर आवाज़ उठा सकें।

■ मछली व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्र करने की जरूरत है। मत्स्य विभाग को इन आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लिए बनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

■ विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण तथा महिलाओं की आवश्यकताओं के बीच समन्वय का अभाव है। सेवा संस्था के साथ मिलकर लोक भागीदारी के विकल्प ढूँढने चाहिए ताकि महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल सके।

■ सभी तकनीकी संस्थाओं को चाहिए कि वे ज्यादा-से-ज्यादा महिलाओं तक पहुंचें तथा उन्हें व्यवसाय प्रबन्धन और गुणवत्ता नियंत्रण की जानकारी दें। CSR संस्था इसमें सहयोग कर सकती हैं।

■ खुदरा व्यापारियों के लिए बने कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि इन व्यापारियों को छायादार स्थान, शौचालय पानी की सुविधा मिल सकें साथ ही उन्हें उनकी जगह से मनमाने ढंग से बेदखल न किया जा सके।

इस जनसुनवाई में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रहें—

■ जस्टिस एम. आर. हरिहरण (समिति के मुखिया)

■ मत्स्य ऋण राहत विभाग के प्रधान

■ मिस अनुपमा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त (आई.ए.एस./प्रशासनिक अधिकारी)

■ डॉ.के.ऐम्बेडी, तटीय विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध निर्देशक

■ श्री किशोर कुमार, मत्स्यफेड के प्रबन्ध निर्देशक

■ मिस लेथी, मत्स्य विभाग की अतिरिक्त निर्देशक

■ मिस सुजाथा विश्वनाथन, इन्चार्ज सचिव, मालवाहक मजदूर बोर्ड

■ डॉ. निकिता गोपाल, केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक

■ श्री.ए.जे.विजयन, सामाजिक कार्यकर्ता

